

# राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर - 19,

नया रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल: seiaacg@gmail.com

1301

क. / एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग./ कोल.बेनि./ कोरबा/03 नया रायपुर दिनांक 20 / 01 / 2017  
प्रति,

मेसर्स इन्डस उद्योग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड,  
ग्राम-जमनीपाली,  
तहसील-करतला,  
जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषय :- खसरा नं. 141/1, 411/4ख एवं अन्य, कुल क्षेत्र 20.55 एकड़,  
ग्राम-जमनीपाली, तहसील-करतला, जिला-कोरबा, कोल वॉशरी उत्पादन  
क्षमता-0.9 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) की स्थापना हेतु  
पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका ऑनलाईन प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/  
1871/ 2015, दिनांक 19/09/2016 एवं अनुवर्ती पत्राचार दिनांक  
09/12/2016

—:: 00 ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया पत्र दिनांक 19/09/2016 एवं 09/12/2016  
का अवलोकन हो।

- ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 1871/ 2015, यह आवेदन दिनांक 19/09/2016 के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त हुआ है।
- प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत खसरा नं. 141/1, 411/4ख एवं अन्य, ग्राम-जमनीपाली, तहसील-करतला, जिला- कोरबा, कुल क्षेत्र -20.55 एकड़ में कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता-0.9 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 1200 लाख है।
- एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 26/11/2015 के द्वारा स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता-0.90 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) वेट टाईप हेतु जारी किया गया।
- लोक सुनवाई दिनांक 29/06/2016 को स्थान-आदिम जाति कल्याण विभाग, पूर्व माध्यमिक शाला, जमनीपाली, ग्राम-जमनीपाली, तहसील-करतला, जिला-कोरबा में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गयी। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पत्र दिनांक 28/07/2016 द्वारा प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट पत्र दिनांक 14/09/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 206वीं बैठक दिनांक 19/10/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया था कि :-

1. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में जोड़े गये अतिरिक्त बिन्दु का पालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही की कार्य योजना मंगाया जावे।
2. फाईनल ले आउट प्लान प्रस्तुत किया जावे।
3. फाईनल ले-आउट प्लान में वृक्षारोपण को नक्शे में दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या, क्षेत्रफल एवं कार्ययोजना जानकारी मंगाया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारीयों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/12/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

**समिति द्वारा विचार** — एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 211वीं बैठक दिनांक 09/12/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री रूपेश गर्ग एवं श्री नितेश अग्रवाल, डायरेक्टर तथा मेसर्स एनाकॉन लेवोरट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर की ओर से डॉ. डी. जी. गारबे, डायरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. स्थल का खसरा नं. 141/1, 411/4ख एवं अन्य, कुल क्षेत्र 20.55 एकड़, ग्राम-जमनीपाली, तहसील-करतला, जिला-कोरबा में स्थित है। उक्त में से 6.06 एकड़ भूमि कंपनी के स्वयं के नाम पर है, शेष 14.49 एकड़ भूमि कंपनी द्वारा भूमि स्वामियों से लीज में प्राप्त की गई है। 12.43 एकड़ भूमि कंपनी के संचालक, श्री सुखसाय पैकरा से लीज पर प्राप्त की गई है। शेष 2.06 एकड़ भूमि श्री रमेश कुमार पटेल एवं श्री दिनेश कुमार पटेल से लीज में प्राप्त की गई है। समीपस्थ आबादी ग्राम-जमनीपाली 0.6 कि.मी. , रेल्वे स्टेशन 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्य मार्ग 1.05 कि.मी. है। समीपस्थ हसदेव नदी 4.5 कि.मी., सोन नदी 0.9 कि.मी., कर्रा नाला 6.7 कि.मी., बेंदो नाला 3.6 कि.मी., बलगुरिया नाला 3.1 कि.मी. है। कोल वॉशरी स्थल से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर मेसर्स मड़वा पॉवर प्लांट एवं 4.5 कि.मी. की दूरी पर मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पॉवर प्लांट स्थित है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्वाट्रिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. ग्राम पंचायत जमनीपाली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 07/06/2012 के द्वारा कोल कशिंग इकाई क्षमता 05 लाख मीट्रिक टन / वर्ष हेतु सम्मति प्रदान की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी दी गई कि कोल कशिंग इकाई में उत्पादन दिनांक 08/08/2016 से प्रारंभ किया गया है।
5. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में जोड़े गये अतिरिक्त बिन्दु का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
6. कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता- 0.9 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) है। वेत कोल वॉशरी हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित स्थापित किया जायेगा। रॉ-कोल की मात्रा 0.9 मिलियन टन/ वर्ष, वाशड कोल की मात्रा 0.675 मिलियन टन/ वर्ष, रिजेक्ट कोल की मात्रा 0.198 मिलियन टन / वर्ष है। वॉशरी से 85 प्रतिशत रॉ कोल एवं वाशड कोल का परिवहन उद्योगों तक रेल मार्ग द्वारा एवं शेष 15 प्रतिशत

उद्योगों तक सड़क मार्ग द्वारा किया जायेगा। रिजेक्ट कोल का पूर्णतः परिवहन सड़क मार्ग द्वारा किया जायेगा।

7. **जल उपयोग की मात्रा** – परियोजना में प्रतिदिन लगभग 3472 घनमीटर/दिन (कोल वाशिंग 3440 घनमीटर/दिन (मेकअप वाटर कोल वाशिंग 518 घनमीटर/दिन), डस्ट सप्रेशन 23 घनमीटर/दिन, प्लांटेशन 06 घनमीटर/दिन, डोमेस्टिक 03 घनमीटर/दिन) जल खपत होगा। जल की आपूर्ति भू-जल से किया जावेगा। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, नई दिल्ली में 550 किलोलीटर /दिन भूमिगत जल दोहन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
8. **दूषित जल उपचार व्यवस्था** – वॉशरी प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न दूषित जल को थिकनर में उपचारित किया जावेगा। उपचार उपरांत दूषित जल का पुनः वॉशिंग हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।
9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोल क्रशर में बैग फिल्टर स्थापित किया जायेगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जावेगा। सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंका जायेगा। कोल वॉशरी से उत्पन्न ध्वनि स्तर के नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्था किया जावेगा तथा कर्मचारियों को ईयर प्लग भी उपलब्ध कराया जायेगा।
10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – कोल वॉशरी से मुख्यतः रिजेक्ट कोल 600 टन / दिन (198000 टन/वर्ष), स्लज (थिकनर से) 1.8 टन/ दिन, स्पेंट ऑयल एवं ग्रीस 0.5 किलोग्राम/दिन तथा घरेलु अपशिष्ट 04 किलोग्राम/दिन ठोस अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होगा। उद्योग से ठोस अपशिष्ट के रूप में शेल एण्ड सेंड स्टोन एवं हवी मीडिया लगभग 27000 टन/वर्ष उत्पन्न होगा। इसका उपयोग भूमि भरण अथवा सड़क निर्माण में किया जायेगा। वॉशरी रिजेक्ट की मात्रा 198000 टन/वर्ष होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट कोल का उपयोग स्वयं के पावर प्लांट में एवं समीपस्थ सी.एफ.बी.सी. आधारित पावर प्लांट में किया जावेगा। थिकनर से प्राप्त स्लज को डि-वॉटरिंग कर वॉशरी रिजेक्ट में मिलाकर उपरोक्तानुसार ईंधन के रूप में उपयोग किया जावेगा।
11. उद्योग द्वारा ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। रेल्वे साईडिंग से लोडिंग अनलोडिंग के दौरान फ्यूजिटिव डस्ट के उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु अवरोध दीवार के रूप में 3 मीटर (10 फुट) की उंचाई का गेल्वेनाईज्ड कारुगेटेड मेटल शीट एवं फिल्टर स्क्रीन की स्थापना किया जावेगा। साथ ही रेल्वे साईडिंग के एलॉग ग्रीन बेल्ट का विकास किया जावेगा। वर्तमान में रेल्वे साईडिंग के एलॉग 4.5 मीटर चौड़ा वृक्षारोपण किया जा चुका है। परियोजना परिसर के चारों तरफ 6.89 एकड़ भूमि में (कुल परियोजना भूमि के क्षेत्रफल का 33.5 प्रतिशत भूमि) वृक्षारोपण किया जावेगा।
12. **मॉनिटरिंग का कार्य** अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तक किया गया। परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन 09 स्थलों पर, सतही जल गुणवत्ता मापन 06 स्थलों पर, भू जल गुणवत्ता मापन 05 स्थलों पर, ध्वनि स्तर मापन 09 स्थलों पर, मृदा गुणवत्ता मापन 09 स्थलों पर किया गया। प्राप्त परिणामों के अनुसार परिवेशीय वायु में पीएम<sub>10</sub> 40 से 70 माईक्रोग्राम /घनमीटर, पीएम<sub>2.5</sub> 13 से 24 माईक्रोग्राम /घनमीटर, एस.ओ.<sub>2</sub> 6.0 से 12 माईक्रोग्राम /घनमीटर एवं एन.ओ.<sub>एक्स</sub> 8.0 से 20 माईक्रोग्राम /घनमीटर है। सतही जल की गुणवत्ता में औद्योगिक प्रदूषण का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। उद्योग में मशीनरी एवं परिवहन से ध्वनि स्तर लगभग 90 डीबीए के भीतर होगा। “ध्वनि” न्वाइस मॉडल का उपयोग कर ध्वनि स्तर का आकलन किया गया है। ध्वनि स्तर उद्योग परिसर में 54.3 डीबीए तथा ग्राम – जमनीपाली में 44.9 डीबीए है। आकलन के आधार पर ग्राम –

जमनीपाली में इन्क्रीमेंटल ध्वनि स्तर 46.3 डीबीए होगा। अर्थात् परियोजना के आने से ग्राम – जमनीपाली के परिवेशीय ध्वनि स्तर में 1.4 डीबीए वृद्धि होना संभावित है।

13. अधिकांश वॉशड कोल का परिवहन रेल मार्ग से किया जावेगा। 85 प्रतिशत रॉ कोल का परिवहन रेल मार्ग से (लगभग 2318 टन/दिन) किया जावेगा। शेष 15 प्रतिशत रॉ कोल (लगभग 409 टन/दिन) तथा रिजेक्ट कोल 600 टन/दिन को वाहनों से सड़क मार्ग से परिवहन किया जावेगा। फलस्वरूप 25 टन क्षमता के लगभग 43 वाहनों का परिवहन में प्रतिदिन उपयोग किया जावेगा, जिससे सड़क मार्ग पर कोल परिवहन से प्रभाव नहीं पड़ना बताया गया है।
14. परियोजना हेतु कुल 0.49 मेगावॉट विद्युत खपत होना संभावित है, विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 350 के.व्ही.ए. क्षमता का एक डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
15. उद्योग द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट में सामाजिक कल्याण विकास के मद में दर्शायी गई राशि रूपए 29.3 लाख “स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस” के अनुसार “इंटरप्राइजेस सोसल कमिटमेंट (आईएससी)” हेतु निर्धारित परियोजना की स्थायी पूंजी लागत (लगभग 11.50 करोड़ रुपये) के आधार पर 2.5 प्रतिशत के अनुसार है। इस राशि को सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु व्यय किया जावेगा। यह राशि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अर्जित लाभ से “कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी” हेतु व्यय की जाने वाली राशि से भिन्न एवं पृथक राशि है। पर्यावरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुरूप प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु यह राशि व्यय की जाएगी।
16. उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही की निगरानी एवं अन्य कोल वॉशरी से होने वाले किसी समस्या के निराकरण हेतु स्थानीय पर्यावरण प्रभाव निगरानी समिति का गठन किया जावेगा। जिसमें गांव के प्रमुख व्यक्तियों यथा सरपंच या पंच, ग्राम सचिव, शिक्षक, उद्योग के प्रतिनिधि, श्रमिक प्रतिनिधि इत्यादि को शामिल किया जावेगा। इस समिति की बैठक नियमित रूप से की जावेगी एवं कोल वॉशरी के संचालन से पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी दुष्प्रभाव तथा ग्रामीणों को इस कारण से होने वाले किसी भी समस्या के समाधान हेतु आपसी बातचीत के द्वारा हल निकाला जावेगा।
17. उद्योग परिसर से लगभग 01 कि.मी. की दूरी पर ग्राम जमनीपाली में ‘साधु तालाब’ स्थित है। यह तालाब उद्योग के परिवहन मार्ग में स्थित नहीं है। वर्तमान कोयला कशिंग इकाई के संचालन एवं विचाराधीन कोल वॉशरी की स्थापना एवं संचालन के फलस्वरूप इस तालाब की जल गुणवत्ता पर किसी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावना नहीं हैं। जिला कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा के पत्र क्रमांक 8601, दिनांक 05/07/2016 में स्पष्ट किया गया है कि साधू तालाब का निरीक्षण किया गया किन्तु वहां किसी भी प्रकार का कोल डस्ट, राखड एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण नहीं पाया गया, तालाब में निरीक्षण में भी जन जीवन सामान्य पाया गया तथा तालाब उद्योग परिसर से काफी दूर पर मौजूद है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रदूषण के होने की आशंका नहीं है।

● **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं :-**

1. कोल वाशरी स्थापना करने के पूर्व शासन के नियमानुसार आवश्यक जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना की जावे।
2. उद्योग परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जावे।

3. उद्योग की स्थापना के पश्चात कोल वाशरी संयंत्र के आसपास निवासरत ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया जावे।
4. उद्योग प्रबंधन द्वारा ग्राम जमनीपाली एवं आसपास के क्षेत्र का सामुदायिक विकास किया जावे।
5. कोल वाशरी के स्थापना से ग्राम जमनीपाली की कृषि भूमि बंजर होगी। साथ ही ग्राम जमनीपाली की जनता साग-सब्जी उगाकर के अपना भरण पोषण करती है। जमीन बंजर होने से सब्जी की पैदावार नहीं होगी।
6. साधु तालाब का पानी संबंधित उद्योग के कशर से दूषित हो गया है। अगर कोल वाशरी की स्थापना होगी तो साधु तालाब का जल पूर्णरूपेण से प्रदूषित हो जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों की वस्तुस्थिति एवं उद्योग प्रबंधन के कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

1. कोल वाशरी परियोजना में शासन के दिशा-निर्देशों के तहत जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरणों की स्थापना की जाएगी। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कशर के सभी ट्रांसफर पाइंट पर बैग फिल्टर, कोल हैण्डलिंग प्लांट में जल छिड़काव, रेल्वे साइडिंग में कोयले के लोडिंग/अनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान जल छिड़काव किया जावेगा। साथ ही जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु थिकनर का उपयोग किया जावेगा। तत्पश्चात संपूर्ण उपचारित दूषित जल को पुनर्चकित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट का निर्माण किया जावेगा।
2. संयंत्र प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट अनुसार 6.89 एकड़ अर्थात् 33 प्रतिशत क्षेत्र में लगभग 5580 नग पौधा रोपण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त रेल्वे साइडिंग स्थल के आसपास हरित पट्टिका के रूप में 680 नग पौधों का रोपण किया गया है।
3. कोलवाशरी स्थापना के पश्चात स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दी जावेगी। अधिकतम रोजगार आसपास के स्थानीय ग्रामीणों को दिया जावेगा।
4. उद्योग प्रबंधन द्वारा सी.एस.आर मद के तहत ग्राम जमनीपाली एवं आसपास के ग्रामों में सामुदायिक विकास का कार्य किया जावेगा। जिसके अंतर्गत चिकित्सालय, शिक्षा, पेयजल, तालाब सौंदर्यकरण आदि का कार्य किया जाकर ग्रामों के विकास में योगदान किया जावेगा।
5. कोल वाशरी में वेट वाशिंग प्रोसेस अपनाई जावेगी। जिससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। उद्योग के संपूर्ण दूषित जल का पुनर्उपयोग किया जावेगा। किसी प्रकार का दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर एवं कृषि भूमि में नहीं किया जावेगा। अतः कृषि भूमि के बंजर होने की संभावना नहीं है। ग्रामवासी कृषि कार्य पूर्वानुसार कर सकते हैं। उद्योग प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों द्वारा सब्जी के उत्पादन में तकनीकी/वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।
6. कशर के ट्रायल संचालन के दौरान होने वाले प्रदूषण के संबंध में ग्रामीणजन से प्राप्त शिकायत के प्रति संज्ञान लेते हुए कशर का संचालन बंद कर दिया गया है। कोल वाशरी की स्थापना के पश्चात कोल कशर में वेट प्रक्रिया अपनाई जावेगी। जिससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। साथ ही साधु तालाब पर भी प्रदूषण का प्रभाव नहीं होगा। इसके

अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा साधु तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जावेगा, जिससे ग्रामीणजन को तालाब से लाभ प्राप्त हो सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 141/1, 411/4ख एवं अन्य, कुल क्षेत्र 20.55 एकड़, ग्राम-जमनीपाली, तहसील-करतला, जिला-कोरबा, कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता-0.9 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की 68वीं बैठक दिनांक 04/01/2017 में चर्चा की गई। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खसरा नं. 141/1, 411/4ख एवं अन्य, कुल क्षेत्र 20.55 एकड़, ग्राम-जमनीपाली, तहसील-करतला, जिला-कोरबा, कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता-0.9 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार खसरा नं. 141/1, 411/4ख एवं अन्य, कुल क्षेत्र 20.55 एकड़, ग्राम-जमनीपाली, तहसील-करतला, जिला-कोरबा, कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता-0.9 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1) Land requirement shall be 20.55 acres with green belt area minimum 6.89 acres).
- 2) Project proponent shall ensure that annual throughput capacity of the coal washery shall not exceed 0.9 million tonne / annum.
- 3) No water bodies (including natural drainage system) in the area shall be disturbed due to activities associated with the setting up / operation of the washery.
- 4) Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial and domestic effluent. Thickener followed by sedimentation ponds of adequate capacity shall be provided for treatment of industrial effluent. Domestic effluent shall be treated in septic tank and soak pits. Project proponent shall provide effluent treatment plant before commissioning of the washery. Treated / un-treated effluent collection pond shall be lined suitably to prevent seepage into ground for avoiding ground water contamination. All the effluent treatment system shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India or Chhattisgarh Environment Conservation Board, Naya Raipur (whichever is stringent).
- 5) Any liquid effluent what so ever generated from industrial activities shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within premises. All the industrial effluent generated shall be re-circulated / reused after proper treatment. The un-treated / treated domestic effluent shall not be discharge into the river or any surface water bodies. The treated domestic effluent shall be used for plantation purpose after proper disinfection. Project proponent shall make proper arrangements of suitable drains / pipe networks to ensure adequate flow for utilization of treated effluent inside the premises. The concept of zero discharge shall be maintained all the time except during monsoon. Arrangements shall be made that effluents and storm water do not get mixed.

- 6) Project proponent shall provide adequate measuring arrangements for the measurement of water utilized in different categories and effluent generated before commissioning of the washery.
- 7) Water consumption shall not exceed 3472 cum / day (Coal washing – 3440 cum / day (makeup water – 518 cum / day), dust suppression – 23 cum / day, Plantation – 06 cum / day and domestic – 03 cum / day). Water will be sourced from ground water after obtaining approval of Central Ground Water Authority. Water requirement shall be optimized. Wet process based on closed water cycle system shall be adopted. Minimum water drawl for makeup purposes shall be ensured.
- 8) Project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements such as bag filters at all point and non point sources for the control of emissions from processes / operations and for the control of emissions during the handling & transportation of raw coal / rejects etc. before commissioning of the washery and maintain in proper order during operation. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Project proponent shall establish wind braking wall & dust suppression systems along railway siding and towards railway track to ensure control of fugitive dust emission. The particulate emissions from any point source shall not exceed 50 mg / Nm<sup>3</sup> under any circumstances. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the industry, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency.
- 9) At-least 85% of the coal shall be transported through rail. During the transportation of raw coal / rejects by road, the project proponent shall maintain fugitive dust emissions to the minimum level in the areas of road transportation routes to ensure compliance National Ambient Air Quality Standards prescribed including black topping / asphaltting / concreting and maintenance with requisite water sprinkling arrangements. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transporting the mineral shall be covered with tarpaulins and optimally loaded. The project authority shall obtain permission from competent authority of State Government for use of roads for transportation of raw coal, washed coal, reject / fines etc. through roads.
- 10) Adequate number of permanent ambient air quality monitoring stations (not less than four) in the core zone as well as buffer zone for PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub> and SO<sub>2</sub> shall be set-up in the down wind direction as well as where maximum ground level concentrations are anticipated in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Monitoring network shall be designed taking into account the environmentally and ecologically sensitive targets, land use pattern, location of the stacks, meteorological conditions and topographic features including existing ambient air quality data. The data so collected shall be properly analyzed and submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Naya Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Korba, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur in every six months.
- 11) Project proponent shall install separate electric metering arrangements with time totalizer and interlocking arrangement for the running of pollution control device(s). These arrangements shall be made in such a fashion that any non-

functioning of pollution control device / devices shall immediately stop the electric supply to the raw coal supply system and shall remain tripped until the pollution control device / devices are made functional again / rectified to achieve the desired efficiency.

- 12) The raw coal, washed coal and coal wastes (rejects) shall be stacked properly at earmarked site (s) within stockyards fitted with wind brakers / shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored minerals do not catch fire.
- 13) Project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Project proponent shall obtain authorization from Board for management and handling of hazardous materials as per Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (if required).
- 14) All the internal roads shall be made pucca before commissioning of the washery. The project proponent shall adopt good housekeeping practices. The roads shall be regularly cleaned. Avenue plantation shall be developed along the roads. Facilities for parking of vehicles / trucks carrying coal, waste rejects etc. shall be created within the unit premises. No public place shall be used for parking of vehicles / trucks.
- 15) Project proponent shall take proper action to control the noise pollution. Project proponent shall install appropriate noise barriers / control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation to control the noise. Earplugs / ear muffs etc. shall be provided to the employee working in the high noise areas. The noise level shall not exceed the limits 75 dB (A) during the day-time and 70 dB (A) during the night-time within the factory premises. Project proponent shall take adequate measures for control of noise level below 85 dB (A) in the work environment. Workers engaged in noisy areas shall be periodically examined to maintain audiometric record and for treatment for any hearing loss including rotating them to non-noisy / less noisy areas.
- 16) Project proponent shall provide appropriate arrangements to avoid air pollution, water pollution, noise pollution etc. during construction phase and during transportation of plants / machineries / equipments / construction materials etc. to the propose site. For controlling fugitive dust during transportation and construction works, regular sprinkling of water in village roads and other vulnerable areas of the plant shall also be ensured. The emission from vehicles engaged for transportation of plants / machineries / equipments / construction materials etc. to the site shall be ensured within prescribed vehicle emission norms. First aid and sanitation arrangements shall be made for the drivers and other contract workers during construction phase.
- 17) The construction of effluent treatment plant and installation of air pollution control equipments shall be taken up simultaneously with other civil / mechanical works at the propose site. The progress of the activities related to the project shall be submitted periodically to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Naya Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Korba, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Nagpur.
- 18) Project proponent shall provide adequate number of influent and effluent quality monitoring stations / points in consultation with Chhattisgarh Environment Conservation Board. Regular monitoring shall be carried out for relevant parameters. Regular monitoring of surface and ground water quality including heavy metals (Hg, Cr, As, Pb) shall be undertaken and the project area to



ascertain the change in the water quality, if any, due to leaching of contaminants from disposal area / project area. Result and data collected shall be analyzed to ascertain the status of water quality and findings shall be submitted. Continuous monitoring of ground water level and quality shall be carried out by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers at suitable locations at the proponent's cost in and around project area in consultation with Regional Director, CGWB, Central Region, Bhopal.

- 19) Adequate safety measures shall be provided in the plant area to check / minimize spontaneous fires in raw coal yard, rejects yard etc. especially during summer season. Copy of the these measures with full details along with location plant layout shall be submitted to Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Bilaspur, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.
- 20) At least 6.89 acres (about one third of the total plant area) shall be used for green belt development. Width of green belt shall not be less than 15 meter all along the boundary of the plant premises. Project proponent shall also develop thick green belt along railway siding and towards railway track. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that at-least three years old plants shall be planted for green belt development. Project proponent shall abide by the decisions taken by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India / Central Government/ Central Pollution Control Board / State Government / Chhattisgarh Environment Conservation Board from time to time in this regard. Tree density of 1500–2000 trees per hectare with local broad leaf species should be maintained.
- 21) Project proponent shall provide garland drains with appropriate check dams all along the raw coal, dust, washery rejects dump / storage areas etc. to avoid any possibility of erosion (wearing away) during rain. Garland drain (size, gradient & length) and sump capacity shall be designed keeping 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the project site. Sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains. Project proponent shall provide adequate collection and treatment arrangement for proper management of storm water. The surface run-off shall be de-silted through a series of check dams and drains. The storm water shall be collected in storage tanks and used for industrial purpose, so as to reduce the ground water consumption.
- 22) The project proponent shall also comply with all the environment protection measures and safeguards recommended in the EIA/EMP report. Further, the company must undertake socio-economic development activities in the surrounding village like community development programme, educational programmes drinking water supply and health care etc.
- 23) Project proponent shall adopt the code of practice for coal washeries issued by Central Pollution Control Board.
- 24) Project proponent shall adopt rainwater-harvesting technique in the project area and residential area (if any) for recharge of ground water. The rainwater-harvesting technique shall be incorporated right from the design stage of all structures. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures to harvest the rainwater for utilization in the lean season as well as to recharge

the ground water table. A detailed scheme for rainwater harvesting to recharge the ground water aquifer shall be prepared in consultation with Central Ground Water Authority / State Ground Water Board. A copy of the same shall be submitted within three months to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Naya Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Korba, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.

- 25) Project proponent shall establish an environmental management cell to carryout function relating to environmental management under the supervision of senior executive who would directly report to the head of organization. A full-fledged laboratory with qualified technical / scientific staffs to monitor the influent, effluent, ground water, surface water, soil, stack emission and ambient air quality etc. shall be provided.
- 26) Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crutch etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- 27) Occupational Health Surveillance of the all workers shall be done on a regular basis i.e. at-least once in a year and records maintained as per the factories act.
- 28) Project proponent shall also ensure the availability of adequate pastureland for cattle feed after acquisition of land. Project proponent shall also facilitate the respective Gram Panchayats for development of alternative pastureland for cattle feed in the villages as per demand of concerning Gram Panchayat(s).
- 29) Adequate funds shall be allocated for undertaking CSR activities. Project authority must undertake socio-economic development activities in the surrounding villages like community development programmes, educational programmes, drinking water supply and health care etc. Local laboures shall be given employment during construction and operation of the plant.
- 30) SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to revoke the clearance if conditions stipulated are not implemented to the satisfaction. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to amend / cancel any of the conditions and add new conditions and make further stringent the emission / effluent limit as and when deemed necessary in the interest of environmental protection, change in the project profile or non-satisfactory implementation of the stipulated conditions etc.
- 31) The project proponent shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India at [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) and website of SEIAA, Chhattisgarh at [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org).
- 32) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad / Municipal Corporation, urban local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions / representations, if any, received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.

- 33) Half yearly report on the status of implementation of the stipulated conditions and environment safeguards shall be submitted to the Chhattisgarh Environment Conservation Board, Naya Raipur, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Korba, SEIAA, Chhattisgarh and Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Nagpur.
- 34) Regional Office of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change at Nagpur will monitor the implementation of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report and Environment Management Plan along with the additional information submitted from time to time shall be forwarded to the Regional Office for their use during monitoring. Project proponent will up-load the compliance status in their website and up-date the same from time to time at least six monthly basis.
- 35) The project authority shall constitute a monitoring committee comprising of representatives of all stake holders i.e. Gram Panchayat, villagers, workers, transporters and management etc. This committee shall monitor the conditions stipulated in the environmental clearance, environmental protection measures adopted, socio-economic development activities / community development programmes undertaken etc. The committee shall monitor the above matters at-least once in a month; during which, factual situation regarding above matters will be discussed. The proceedings of the committee shall be recorded in writing along with suggestions (if any). Project management shall take immediate action on the basis of observations / suggestions of the committee. A copy of the proceedings of the committee shall be submitted to Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Korba for information.
- 36) The project authorities shall inform the Regional Office as well as the SEIAA, Chhattisgarh regarding the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities and the dates of start of land development work and commissioning of washery.
- 37) Full cooperation shall be extended to the Scientists / Officers from the SEIAA, Chhattisgarh, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India /Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Nagpur / the CPCB / the Chhattisgarh Environment Conservation Board, who would be monitoring the compliance of environment status.
- 38) In case of any deviation or alteration in the proposed project from those submitted to this SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India / SEIAA, Chhattisgarh.
- 39) Concealing factual data or submission of false / fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- 40) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- 41) The above stipulations would be enforced among others under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control

of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and rules there under, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, the Public Liability Insurance Act, 1991 and its amendments. The proponent shall ensure to provide for the costs incurred for taking up remedial measures in case of soil contamination, contamination of groundwater and surface water, and occupational and other diseases due to the washery operations.

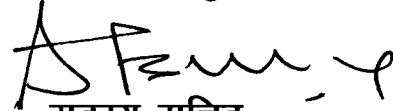
- 42) The issuance of this environmental clearance does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does not authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.
- 43) Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

  
सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,  
छत्तीसगढ़

पृ. क. <sup>1302</sup> / एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. / कोल.बेनि. / कोरबा / 03 नया रायपुर दिनांक 20 / 01 / 2017  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492001
2. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, द्वितीय मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 100003
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर – 19, नया रायपुर (छत्तीसगढ़)
4. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)
5. कलेक्टर, जिला – कोरबा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,  
छत्तीसगढ़

